

अर्थशास्त्रका नोबेल

मंदी, महंगी और बेरोजगारी किसी एक देशकी समस्या नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरा विश्व इस समस्यासे ग्रसित है। मंदी और महंगीका सीधा सम्बन्ध बेरोजगारीसे है। किसी भी देशके विकास और खुशहालीकी कल्पना तबतक नहीं की जा सकती है जबतक उस देशमें महंगी, मंदी और बेरोजगारीकी जटिल समस्याएं बनी हुई हैं। इस सन्दर्भमें वर्ष २०२६ का अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार अमेरिकाके दो अर्थशास्त्रियों राबर्ट ई.हाल और माइकल वुडफोर्डको उनके शोधके लिए दिया जाना विशेष रूपसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, क्योंकि इन दोनों विद्वानोंने मंदी और महंगीसे निबटनेके लिए दशकोंके प्रयासके बाद एक माडल तैयार किया है। उसका लाभ उठाकर विश्वके ऐसे अनेक देश जो मंदी, महंगी तथा बेरोजगारीकी समस्यासे आक्रान्त हैं, निजात या राहत प्राप्त कर सकते हैं। नोबेल समितिके अनुसार इन अर्थशास्त्रियोंने अपने शोधसे यह निष्कर्ष निकालनेका प्रयास किया है कैसे इस महासंकटसे उबरा जाय। वर्ष २००८ के वैश्विक वित्तीय संकटके बाद केन्द्रीय बैंकोंने जो नीतियां अपनायीं उसमें इस नये माडलकी विशेष भूमिका रही। उनका कार्य बताता है कि पूरी अर्थव्यवस्थाको समझनेके लिए केवल जीडीपी, महंगी या बेरोजगारी जैसे बड़े आंकड़े पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि व्यक्ति और कम्पनियां भविष्यको लेकर क्या सोच रही हैं और उसके आधार आज क्या निर्णय ले रही हैं। राबर्ट हालका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि लोग अपनी आय और भविष्यकी सम्भावनाओंको देखते हुए खर्च और बचतका निर्णय कैसे लेते हैं जबकि माइकल वुडफोर्डने भविष्यकी अपेक्षाओंपर ध्यान केन्द्रित किया है। कम्पनियोंके मूल्य निर्धारण और मौद्रिक नीतिकी विश्वसनीयतापर उन्होंने विशेष जोर दिया है। वुडफोर्डने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकाला है कि मौद्रिक नीति केवल ब्याज दर बदलनेका नाम नहीं है। केन्द्रीय बैंकका संचार भी स्वयं एक आर्थिक उपकरण है। हाल और वुडफोर्डके कार्यको समझनेके लिए १९७० के दशककी अर्थव्यवस्थापर ध्यान देना होगा। उस समय पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओंमें महंगी और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ी थी। इसने लागत बढ़ायी और आर्थिक वृद्धिको भी प्रभावित किया था। हाल और वुडफोर्डके माडल नीति-निर्माताओंको यह समझनेमें सहायता करते हैं कि परिवारों और कम्पनियोंकी अपेक्षाएं किस प्रकार नीतिगत फैसलेको अर्थव्यवस्थामें प्रसारित करती हैं। इसमें विश्वास और भविष्यकी अपेक्षाएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसी तेजीसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाके लिए इस नोबेलका सन्देश विशेष रूपमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत महंगी, रोजगारकी आवश्यकता और विकासकी गतिसे जुड़ी चुनौतियोंका एक साथ समाना कर रहा है। वर्ष २०२६ का अर्थशास्त्रका नोबेल वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्थाके लिए अत्यन्त सामयिक है और इसका लाभ पूरा विश्व उठा सकता है।

मरीजोंके हितमें बड़ा फैसला

केन्द्र सरकारका देशभरके चिकित्सा संस्थानोंको अपनी सेवाओं और सुविधाओंके शुल्क स्पष्ट रूपसे बोर्डपर दर्शानेका निर्देश मरीजों और उनके परिजनोंके हितमें बड़ा और सार्थक कदम है। खास बात यह है कि यह शुल्क बोर्ड ऐसी जगह लगानी होगी, जहां वह सभीको आसानीसे नजर आये। इससे मरीजोंसे मनमाना वसूलीपर अंकुश लगेगा और मरीज तथा तोमारदारोंकी भी पूरी जानकारीमें रहेगा कि किस जांच और सेवाके लिए उसे कितना शुल्क देना है। इस सम्बन्धमें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंको सोमवारको पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है। शुल्क विवरण स्थानीय भाषा और अंग्रेजीमें दिये जानेकी अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। इससे मरीज अथवा उनके परिजनोंको समझनेमें आसानी होगी। केन्द्रका यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि राज्य निम्निकल स्टेबलसिस्मेंट एक्ट वर्ष २०१० में पारित हुआ था और वर्ष २०१२ में इसे अधिसूचित किया गया था, लेकिन अधिकतर राज्योंमें इसके प्रावधान अमलक लागू नहीं हो सके, जो गम्भीर चिन्ताका विषय है। स्वास्थ्य सेवाओंकी मूल्य निर्धारण पारदर्शिता बढ़ाने और मरीजोंको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानेके लिए केन्द्रकी पहल स्वागतयोग्य है लेकिन यह कागजोंतक ही सिमटकर न रह जाय, इसपर विशेष ध्यान देनेकी जरूरत है। इसपर सतत निगरानी रखी जानी चाहिए। चिकित्सा संस्थानोंमें जिस तरह मरीजोंके शोषणकी घटनाएं देखने-सुननेको मिल रही हैं वह मानवीय संवेदनाओंको तार-तार करने वाली हैं। इसपर प्रभावी अंकुश लगना चाहिए। व्यापक पारदर्शितासे न केवल अनावश्यक बिलसे जुड़े विवाद कम करनेमें मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालीमें भी लोगोंका भरोसा और विश्वास बढ़ेगा। सरकारने यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और मरीजोंको अच्छी स्वास्थ्य सेवा देनेके उद्देश्यसे उठाया है जिसका सार्थक परिणाम धरातलपर दिखना चाहिए।

लोक संवाद

ब्रिटेन छोड़कर भाग रहे अरबपति

महोदय,-ब्रिटेनके कई धनाढ्य कारोबारी और अरबपति देशकी बढ़हाल व्यवस्था और नीतियोंसे परेशान होकर अब ऐसे देशोंका रुख कर रहे हैं, जहां की अर्थव्यस्था एवं परिस्थितियां उनके लिए अधिक अनुकूल हैं।ऐसेमें अमीर निवेशकोंको स्विट्जरलैंड, मोनाको, ग्रीस और दुबई जैसे ठिकाने आकर्षित कर रहे हैं। ब्लूमबर्गकी रिपोर्टके मुताबिक इस रुझानसे ब्रिटेनकी वैश्विक वित्तीय केन्द्रके रूपमें प्रतिष्ठा और वहाके संपत्ति कारोबारपर असर पड़नेकी चिन्ता बढ़ी है। हालांकि उपलब्ध सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करमें विशेष छूट लेने वाले धनी विदेशी निवासियोंकी संख्यामें कुल गिरावट अबतक सीमित रही है। ब्रिटेनके धनी कारोबारी पहलेसे ही स्विट्जरलैंडके जिनेवा, इटलीके मिलान और मोनाको जैसे ठिकानोंको पसन्द करते रहे हैं।अब कुछ दूसरे देश भी उन्हें आकर्षित कर रहे हैं।हालांकि सभी कारोबारी केवल कर बचानेके लिए ही देश नहीं बदलते। उनके फैसलोंमें जीवनशैली, बच्चोंकी शिक्षा, उत्तराधिकार कानून, सांस्कृतिक गतिविधियां और कारोबारके अवसर भी अहम भूमिका निभाते हैं। तेल कारोबारी पियररे आंद्राने दुबईका रुख किया, जबकि अरबपति रे डालियोंने अबू धाबीमें अपना पारिवारिक निवेश कार्यालय स्थापित किया है। रिपोर्टके अनुसार ग्रीस कुछ विदेशी आयपर 9५ वर्षतक स्थानीय करसे छूट देता है, जबकि तुर्कियेमें यह लाभ २० वर्षतक मिल सकता है। तुर्कियेमें उत्तराधिकार कर भी अपेक्षाकृत कम बताया गया है। स्पेनमें भी विदेशी पेशेवरोंके लिए विशेष कर व्यवस्था है, जिसे फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहमके नामपर बेकहम कानून कहा जाता है।इसके तहत पात्र लोगोंको एक निश्चित अवधितक विशेष दरसे कर देनेकी सुविधा मिल सकती है। नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देश भी कुछ पेशेवर वर्गोंके लिए कर संबंधी रियायतें देते हैं। ऐसे विकल्प ब्रिटेनके उन कारोबारियोंके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो करके साथ-साथ जीवनशैली और व्यावसायिक सुविधाओंकी तुलना करते हैं। वित्तीय कम्पनियोंने ब्रिटेनमें कारोबार करनेकी लागत और कर संबंधी नियमोंपर सवाल उठाये हैं। माइकल प्लैटकी कम्पनी ब्लूकरेंट कैपिटल मैनेजमेंटने इस वर्ष कहा कि कुछ वरिष्ठ कारोबारियोंके कर निर्धारणपर अवगतमें फैसला आनेके बाद ब्रिटेन अब कारोबारके लिए पहले जैसा आकर्षक विकल्प नहीं रहा। अरबपति एलेक्स गेररको भी कारोवारसे अर्जित कुछ मुनाफेपर करके विवादमें कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। इन घटनाओंने ब्रिटेनकी कर नीतियों और कारोबारी माहौलको लेकर बहस तेज की है। हालांकि कुछ प्रमुख धनाढ्य लोगोंके देश छोड़नेकी खबरोंकी पूरे अमीर वर्गके पलायनका प्रमाण नहीं माना जा सकता।-**आर.पी. सिंह, वाया ईमेल।**

वस्त्र उद्योगका हब बनता भारत

इन दिनों टेक्सटाइल सेक्टरसे संबंधित रिपोर्टोंमें रेखांकित किया जा रहा है कि भारत विश्वके प्रमुख देशोंके साथ हुए एफटीए और सरकार द्वारा

टेक्सटाइल क्षेत्रको दिये जा रहे बहुआयामी प्रोत्साहनोंके दमपर टेक्सटाइलका नया ग्लोबल हब बननेकी राहपर अत्यंत तीव्र गतिसे आगे बढ़ रहा है।

□ डा. जयंतीलाल भंडारी

इंसी वर्ष जुलाई माहमें नयी दिल्लीके भारत मंडपमें आयोजित भारत टेक्स २०२६ ने न केवल वैश्विक टेक्सटाइल जगतमें भारतके लिए एक खर्णिम इतिहास रचा है, बल्कि संपूर्ण विश्वको यह स्पष्ट और सशक्त संदेश भी दे दिया है कि भारत अब वैश्विक वस्त्र आपूर्ति शृंखलाका एक विश्वसनीय, अनिवार्य और प्रमुख ग्लोबल हब बननेकी दिशामें अग्रसर है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके दूरदर्शी ‘५-एफ’ दृष्टिकोण- फार्म (खेत), फाइबर (रेशा), फैक्टरी (कारखाना), फैशन और फोरन (विदेश) को पूरी तरह जीवन करने वाला यह आयोजन दुनियाका सबसे बड़ा एकीकृत टेक्सटाइल मेला बनकर उभरा है।नि:संदेह इस वर्ष २०२६ में देशका टेक्सटाइल सेक्टर लगभग १९० अरब अमेरिकी डालरके बड़े आकारतक पहुंच चुका है, जिसका मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य विजन २०३० के तहत इसे बढ़ाकर ३५० अरब डालरतक ले जाना है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करनेकी दिशामें सरकारकी नयी टेक्सटाइल रणनीति और दुनियाकी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओंके साथ संपन्न हो रहे मुक्त व्यापार समझौते अत्यंत प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकारने बेहद सुनियोजित रणनीतिक तहत इन एफटीए समझौतोंमें टेक्सटाइल सेक्टरको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकोंके लिए दुनियाके सबसे बड़े, संपन्न और विकसित बाजारोंमें शून्य आयात शुल्क प्रवेश (जीरो-ड्यूटी एक्सेस) का सुगम मार्ग निश्चित हो प्रशस्त हुआ है।

इस दिशामें सबसे ऐतिहासिक कदम भारत और ब्रिटेनके बीच १५ जुलाईसे लागू हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीटा) है। इस समझौतेके अंतर्गत ब्रिटेन सरकारने भारतीय टेक्सटाइल और परिधानोंपर पूर्वमें लगने वाले १२ प्रतिशततकके उच्च आयात शुल्कको पूरी तरहसे समाप्त कर दिया है। इस बड़ी और महत्वपूर्ण रियायतके बाद ब्रिटिश बाजारमें भारतीय कपड़े और रेडीमेड गार्मेंट्स हमारे पारम्परिक प्रतिस्पर्धी देशों, जैसे कि बंगलादेश और वियतनामकी तुलनामें अत्यधिक सस्ते, आकर्षक और वाणिज्यिक रूपसे प्रतिस्पर्धी हो गये हैं। इस समझौतेके लागू होने तथा भारतीय निर्यातकोंको उन्नत पूर्व-तैयारीके चरिते वर्तमानमें ब्रिटेनके बाजारोंसे भारतीय टेक्सटाइलकी मांगमें तीव्र और ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त गत एक जूनसे भारत और ओमानके



बीच लागू व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के अंतर्गत ओमानने भी भारतके टेक्सटाइल उत्पादों सहित ९९ प्रतिशतसे अधिक घरेलू उत्पादोंपर आयात शुल्कको पूरी तरहसे शून्य कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनके साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रहे व्यापारिक समझौतोंने पहले ही भारतीय टेक्सटाइल निर्यातको एक नयी ऊँचाई और सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में अप्रैलसे अगस्त २०२६ को अर्वाधिके दौरान भारतका कुल कपड़ा निर्यात १४.९ अरब डालरके आंकड़ेतक पहुंच गया है, जो गत वर्षकी समान अवधिकी तुलनामें सालाना आधारपर १०.३ प्रतिशतकी ठोस वृद्धिको दर्शाता है। इस समयार्वाधिके दौरान काटन टेक्सटाइलके क्षेत्रमें १८.० प्रतिशत, मानव निर्मित वस्त्रोंके क्षेत्रमें १३.६ प्रतिशत और हस्तशिल्पके क्षेत्रमें ४४ प्रतिशतकी उल्लेखनीय संचयी वृद्धि दर्ज की गयी है। वस्त्र निर्यातकोंको वैश्विक प्रतिस्पर्धाके इस दौरमें बड़ी राहत और संबल प्रदान करते हुए सरकारने आरओएससीटीएल योजनाको ३१ दिसम्बर २०२६ तक आगे बढ़ा दिया है, जिससे आगामी वैश्विक त्योहारी सीजनके बड़े ऑर्डर्सको समयपर पूरा करनेमें भारी मदद मिल रही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के ताजा आंकड़ोंके

अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करनेकी दिशामें सरकारकी नयी टेक्सटाइल रणनीति और दुनियाकी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओंके साथ संपन्न हो रहे मुक्त व्यापार समझौते अत्यंत प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकारने बेहद सुनियोजित रणनीतिक तहत एफटीए समझौतोंमें टेक्सटाइल सेक्टरको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकोंके लिए दुनियाके सबसे बड़े, संपन्न और विकसित बाजारोंमें शून्य आयात शुल्क प्रवेशका सुगम मार्ग निश्चित ही प्रशस्त हुआ है।

अनुसार मुख्य कपड़ा उद्योग (यार्न और फैब्रिक) ने अगस्त २०२६ के दौरान १३.१ प्रतिशतकी मजबूत मासिक वृद्धि और चालू वित्त वर्षमें ११.९ प्रतिशतकी शानदार संचयी वृद्धि दर्ज की है।

निश्चित रूपसे गार्टेक्स और ‘भारत टेक्स २०२६’ जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनोंके माध्यमसे देशमें डेनिम लेजर फिनिशिंग और तकनीकी वस्त्रों (टेकिनकल टेक्सटाइल्स) के क्षेत्रमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ऑटोमेशन आधारित स्मार्ट विनिर्माणको बहुत तेजीसे अपनाया जा रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि भारतको दुनियाका सर्वश्रेष्ठ टेक्सटाइल हब बनानेके लिए केन्द्र सरकार ‘पीएम मित्र’ (पीमा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान) योजनाके अंतर्गत देशके सात प्रमुख राज्योंमें सात विशाल और अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करनेकी दिशामें युद्धस्तरपर कार्य कर रही है। देशके इन सभी सात राज्यों (तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) में सी प्रतिशत भूमिका

भारतीय संस्कृतिमें सम्मानकी अवधारणा

सच्चा सामाजिक सुधार तभी निर्मित हो सकता है जब हम आयातित वैचारिक सिद्धांतोंके चश्मेसे भारतीय समाजको देखना बंद करें। सनातन संस्कृतिमें निहित मातृसत्ताकी अवधारणा सम्मान और सह-अस्तित्वपर आधारित है।

□ संजय राय

जब आधुनिक राजनीतिके शीर्ष चेहरे समकालीन मंचोंसे ‘स्मैश द पैट्रियार्की’ (पितृसत्ताका समूल नाश) जैसे आयातित नारोंको भारतीय समाजपर थोपनेका प्रयास करते हैं, तब वैचारिक धरातलपर एक गहरा विरोधाभास उभरता है। पश्चिमी अकादमिक जगतसे उधार ली गयी यह शब्दावली भारतीय मानसपर बल थोपी जा रही है, जब इस देशकी रंगोंमें मातृसत्ताका समान आनादिकालसे बह रहा है। सनातन संस्कृति, इतिहास और भारतके राजनीतिक सफरनामेको टटोलनेपर यह साफ हो जाता है कि जिस नारी-स्वातंत्र्यको पश्चिम आज कानूनी और सामाजिक संघर्षोंके बाद भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया, वह भारतकी मूल चेतनामें सदियोंसे स्थापित है। राजनीतिक रैपिटेड चढ़नेकी होड़में हमारे राजनेता इतिहासके उत बुनियादी सत्योंको भूल जाते हैं जो हमारी पहचानका आधार हैं।

भारतीय उपमहाद्वीपकी सांस्कृतिक यात्रा विश्वकी अन्य सभी सभ्यताओंसे इस मायनेमें अलग है कि यहां ईश्वरत्वको केवल पुरुष रूपमें नहीं, बल्कि सर्वोच्च शक्ति और चेतनाके रूपमें ‘स्त्री’ यानी आदिमाया भगवतीको समान स्वीकारा गया। सनातन परम्परामें किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठानका आरम्भ पुरुष देवताओंकी स्तुतिसे नहीं, बल्कि मातृ शक्तियोंके आह्वांससे होता है। वैदिक विधानके अनुसार, विज्रहतां गणेशकी पूजासे भी पहले ‘गौरी’ की पूजा अनिवार्य है। हमारे शास्त्रोंमें षोडश मातृका (सोलह देवियां) और चौंसठ योगिनियोंका आराधनाका विधान इसका जीवंत प्रमाण है। षोडश मातृकाओंमें गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया और देवसेना जैसी देवियां शामिल हैं, जो बुद्धि, शक्ति, पोषण, संतोष और समाजकी रक्षायी प्रतीक हैं। इसी तरह चौंसठ योगिनियों (जैसे दिव्ययोगिनी, महायोगिनी, सिद्धयोगिनी, कालरात्रि) की संकल्पना ब्रह्महंमांडीय ऊर्जाके उस प्रचंड और गतिशील स्वरूपको दर्शाती है, जहां स्त्री तत्वको सृष्टिके सुजन और नियंत्रणका मुख्य केन्द्र माना गया। यह व्यवस्था पुरुषोंके वर्चस्वके विरोधमें नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि यह पुरुषोंसे आगे बढ़कर मातृसत्ताकी सर्वोच्चताको स्वाभाविक रूपसे स्थापित करती थी।

यह भ्रांति अक्सर सुनियोजित ढंगसे फैलायी जाती है कि प्राचीन भारतमें महिलाओंको ज्ञान और सामाजिक विमर्शसे दूर रखा गया। इसके विपरीत ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्योंको उठाकर देखें तो वहां ऋषिकाओं (महिला ऋषियों) द्वारा रचित ऋचाएं और सूक्त पूरे आदरके साथ समाहित हैं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा और अप्सला जैसी विदुषियोंने न केवल जटिल दार्शनिक बहसोंमें हिस्सा लिया, बल्कि अपनी मेधासे महान ऋषियोंकी भी निरुत्तर किया। सनातनने ज्ञानकी कमान ‘सरस्वती’ को दी, धन और

राष्ट्रीय चेतनाकी अमर धरोहर रामलीला

□ दीपकुमार शुक्ल

यूनेस्को द्वारा विश्वकी अमूर्त धरोहरके रूपमें सूचीबद्ध रामलीलाको परम्परागत लोकनाट्य विधाओंमें सर्वाधिक पटु एवं समृद्ध लोकनाट्य माना जाता है। लगभग एक माहतककी अवधिमें मंचित होने वाली रामलीलाएं भारतीय प्राचीन संस्कृतिके सर्वाभौमिक स्वरूपका दर्शन करानेमें सर्वथा सक्षम हैं। रामलीला मात्र सनातन संस्कृति एवं सभ्यताके उच्च आदर्शोंका निरूपण अथवा भक्तिमय धार्मिक चेतनाके संचरणका साधनभर नहीं है, बल्कि साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतनाके संवेगात्मक प्रवाहोत्कर्षसे भी ओतप्रोत है। रामलीला अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र रामके जीवनसे जुड़ी घटनाओंका मात्र नाट्य रूपांतरण नहीं अपितु भारतीय संस्कृति एवं सभ्यताके उच्च आदर्शोंकी गाथा है। यह गाथा है उच्च मानवीय मूल्यों की। यह गाथा है उच्च आदर्शवादी समाज की। यह गाथा है आदर्शोंके उच्चतम शिखरपर दृढ़तासे खड़ी राजनीतिकी। यह गाथा है आदर्श परिवारकी। यह गाथा है मर्यादाओं-सीमाओंमें बंधे ईमानदार एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व की। रामलीलाका प्रारम्भ किस समय अवधिमें हुआ इसका ज्ञान शायद ही किसीको हो। यह अवश्य कहा जा सकता है कि लोकगीतोंमें रामकथाका गायन जितना पुराना है, रामलीलाकी भी उतना ही प्राचीन मानना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों एवं लोकनाट्योंका अन्तः सम्बन्ध नकारा नहीं जा सकता है। यदि यह कहा जाये कि लोकनाट्य लोकगीतोंका ही नाट्य रूपांतरण है तो अतिसंयोक्त नहीं होगी। सुदूर ग्रामीण अंचलोंमें अपने अस्तित्वको लड़ाई लड़ते रामकथापर आधारित नाट्य सामाजिक एवं आर्थिक जीवन जयेंगेइस प्रकार हमें ‘राजत’ जन समुदाय द्वारा खेले जाने वाले नाटक रामकथापर ही आधारित हैं। उत्तरांचलका लोकनाट्य ‘रम्पान’, गुजरातका ‘भवई’, महाराष्ट्रका ‘ललित’ तथा बंगालका ‘जात्रा’ इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

‘श्रीमद्भारतगीत’ रामायण’ रामकथाका सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना गया है। लवकुश द्वारा रामकथाका गायन भी तभी किया गया था। उसके बादसे रामकथाका गायन किसी न किसी रूपमें निरन्तर होता चला आ रहा है। जो कि संस्कृतके छन्दबद्ध श्लोकों तथा लोकभाषा दोनों ही रूपोंमें प्रचलित हुआ। रामलीलाकी प्रतिष्ठा भी इसीके

अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है तथा आवश्यक पर्यावरण मंजूरियां भी प्राप्त हो चुकी हैं। इन सातों पार्कोंके पूर्ण विकसित और कार्यात्मक हो जानेके बाद देशमें लगभग ७०००० करोड़ रुपयेका कुल निवेश आकर्षित होगा और तत्करीबन २१ लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारके नये अवसर सृजित होंगे। वर्तमान समयमें भी यह संपूर्ण क्षेत्र देशके ५.३ करोड़से अधिक लोगोंको प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही, कपड़ा मंत्रालयकी ‘सामर्थ २.०’ योजनाके तहत देशके युवाओंको आधुनिक मशीनोंपर कुशलतापूर्वक कार्य करनेके लिए री-स्किलिंग और अपस्किलिंगका प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय निर्यातकोंको वैश्विक बाजारमें निरन्तर प्रतिस्पर्धी बनाये रखने और घरेलू विनिर्माणको और अधिक सुदृढ़ करनेके लिए सरकारने कपासके आयातपर लगने वाले सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को अक्टूबर २०२६ तकके लिए पूर्ण रूपसे माफ कर दिया है। वैश्विक स्तरपर प्रचलित ‘चाइना प्लस वन’ रणनीतिके कारण अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक कम्पनियां आज भारतको एक सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक विनिर्माण साझेदारके रूपमें देख रही हैं।

इन्हीं बहुआयामी और दूरदर्शी सुधारोंके परिणामस्वरूप प्रमुख वैश्विक रेटिंग

एजेंसी	आईसीआरएने
भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्रके समग्र परिरुश्यको नकारात्मकसे उन्नत करके स्थिर (स्टेबल) घोषित कर दिया है। इन तमाम अनुकूल परिस्थितियों, सरकारी पहलों और सरकारात्मक आर्थिक संकेतकोंके बावजूद,	भारतीय

टेक्सटाइल सेक्टरके मार्गमें कुछ गम्भीर और संरचनात्मक चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं, जिनपर समय रहते ध्यान देना अनिवार्य है। यद्यपि पिछले वर्ष कच्चे बन्नी (सूत और कपड़े) के निर्यातमें अच्छी वृद्धि दर्ज की गयी है, तथापि तैयार रेडीमेड कपड़ोंके घरेलू उत्पादन एवं निर्यातमें अपेक्षित गति नहीं आ पायी है जिससे कई स्तरोंपर राजस्व वृद्धि सीमित बनी हुई है। देशके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अब भी अपेक्षाकृत महंगी ब्याज दरोंपर ऋण प्राप्त हो रहा है। देशके प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रोंमें आज भी कुशल कारीगरों और तकनीशियनोंकी पर्याप्त कमी महसूस की जा रही है। साथ ही कपासका एक प्रमुख उत्पादक देश होनेके बावजूद भारतकी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता वैश्विक औसतसे काफी नीचे है, जिससे कच्चे मालकी गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित होती है। यदि भारतको वैश्विक वस्त्र-परिधान बाजारमें अपनी हिस्सेदारीको सुदृढ़ करना है तो कई उपाय करने होंगे।



अंतःशुद्धिका महापर्व

□ श्वेता गोयल

नवरात्रि पर्व आदि शक्ति मां दुर्गाकी पूजाका पावन पर्व है।वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी चैत्र तथा आश्विन नवरात्रका ही सर्वाधिक महत्व माना गया है। आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे शारदेयी नवरात्रकी शुरुआत होती है, जिसमें देवी दुर्गाके अलग-अलग रूपोंकी पूजा की जाती है। नवरात्रिके ये नौ दिन पूर्ण रूपसे मां दुर्गा और उनके आठ अलौकिक अवतारोंके पूजनको समर्पित हैं और नवरात्रिका हर दिन इन्हींमेंसे एक अवतारसे जुड़ा है। मां दुर्गाके इन नौ अलौकिक अवतारोंके माध्यमसे सही मायनोंमें आध्यात्मिक उत्कर्षको प्राप्त करना पूर्णतः परिलक्षित होता है। मां दुर्गाके ये नौ रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुम्भाङ्ग, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। मान्यता है कि नवरात्रके इन नौ दिनोंमें मां दुर्गाके अलग-अलग स्वरूपोंकी पूजा करनेसे विशेष पुण्य मिलता है और मां दुर्गा अपने भक्तोंके सभी कष्ट हर लेती हैं। नवरात्रिके संबंधमें एक कथानुसार देवी दुर्गाने महिषासुर नामक असुरके साथ नौ दिनतक युद्ध किया था और नवमीकी रात्रिको ही देवीने उसका वध किया था, तभीसे देवी दुर्गाको महिषासुरमर्दिनीके नामसे भी जाना जाता है। विभिन्न पुराणों एवं शास्त्रोंमें उल्लेख मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामने भी लंका विजयसे पहले मां दुर्गाकी आराधना कर उनसे आशीर्वाद और युद्धके लिए अनुमति ली थी और मां शक्तिके आशीर्वादके कारण ही वे युद्ध जीते थे। शिवपुराणके अनुसार देवी दुर्गाकी उत्पत्ति दुर्गम नामक एक महाबली दुर्गाके मारनेके लिए हुई थी, जिसने ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त करनेके बाद चारों वेदोंको लुप्त कर दिया था। वेदोंके अदृश्य हो जानेसे समस्त वैदिक क्रियाएं बंद हो गयी थी। इन संकटोंके निवारणके लिए सभी देवता महेश्वरी योगमायाकी शरणमें गये और योगमाया देवी दुर्गाने दुर्गासुरका वध किया। मां दुर्गाको अनंतकोटि ब्रह्मांडोंकी अधीश्वरी देवी माना गया है, जो सम्पूर्ण विश्वको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं, जिनकी शक्तिके ही ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है। यह पर्व स्त्रीके स्वयंमें शक्ति होनेका उल्लास भी है और सही मायनोंमें यह पर्व स्त्रीत्वका आनन्दोत्सव ही है।

ही पड़ेगा। जब-जब मानवताको तार-तार करनेका कलुषित प्रयास होगा तथा विक्त मानसिकताएं राष्ट्रके अस्तित्वको चुनौती देंगी। तब-तब सतत संघर्षकी प्रेरणा रामलीलाको ही प्राप्त होगी।

आज रामकथाका मंचसे कहीं अधिक प्रभावी प्रदर्शन दूरदर्शनके विभिन्न चैनलोंपर देखनेको मिल रहा है। आधुनिक कैमरों और कम्प्यूटरके समर्पक्यसे दिखाये जाने वाले दृश्य जहां वास्तविकताके एकदम निकट होते हैं वहीं विभिन्न ग्रन्थों और लोककथाओंसे प्राप्त की गयी शोधधरक जानकारीका नाट्य-रूपांतरण सदियों पुरानी घटनाको और भी अधिक नवीन तथा रोचक बना रहा है। परन्तु रामकथाके उच्च आदर्शोंको समाजमें प्रवाहित करनेकी जो चेतना रमंचवीय रामलीलामें वह दूरदर्शन या ऐसे किसी अन्य माध्यममें प्रतीत नहीं होती है। अतः रामलीलाके मूल स्वरूपको अधुण बनाये रखनेकी महती आवश्यकता है। प्रबुद्ध वर्गकी रामलीलासे होती जा रही विरक्तिके कारण इसका संचालन धीरे-धीरे उन हाथोंमें पहुंच रहा है जो इसे मनोरंजनका साधन बनाना चाहते हैं। जिससे रामलीलाके मूल स्वरूपका क्षरण होना स्वाभाविक है। अतएव प्रबुद्ध वर्गको इसे अपना सामाजिक दायित्व समझकर इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपनी सतत भूमिका सुनिश्चित करनी ही चाहिए। वर्ष २००५ में यूनेस्को द्वारा रामलीलाको विश्वकी अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था।

अतः सरकारी स्तरपर रामलीलाके संरक्षण संवर्धनके लिए विशेष कार्य-योजनाएं बननी चाहिए थीं। परन्तु दुर्भाग्यसे किसी भी सरकारने आजतक ऐसा कुछ भी नहीं किया। त्रिनिडाड और टोबैगोमें रामलीलाके संरक्षण, संवर्धन और आयोजनके लिए सबसे प्रमुख संस्था नेशनल रामलीला कार्टिसिल आफ त्रिनिडाड एण्ड टोबैगोकी वहांकी संसद द्वारा पारित अधिनियम २०१२ के तहत आधिकारिक रूपसे स्थापित किया गया है। इस परिपदके अन्तर्गत देशके विभिन्न हिस्सोंके लगभग ३५ से अधिक स्थानीय रामलीला समूह वजीकृत हैं। यह परिपद इन सभी समूहोंको आपसमें जोड़ने और वार्षिक प्रदर्शनोंको योजना बनानेका काम करती है। केवल रामलीलाका मंचन ही नहीं कराती, बल्कि यह विश्वविद्यालयों और भारतीय उच्चशिक्षा के साथ मिलकर रामलीला हेरिटेज सिम्पोजियम (विरासत संगोष्ठी) और शोध कार्योंका भी आयोजन करती है। ताकि आने वाली पीढ़ीको इसके इतिहाससे अवगत कराया जा सके। भारत सरकारको भी कुछ ऐसी ही पहल करनी चाहिए।